INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 29 नवंबर से 05 दिसंबर 2025

भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित

अंक-68

मूल्य- रु. 5 /-

आईएमएफ का अनुमान: वित्त वर्ष 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.6%, 27 में 6.2% रहेगी

वैश्विक व्यापार तनाव के बीच मजबूत घरेलू मांग से रेटिंग, FY26 के लिए 0.2% की बढ़ोतरी; FY27 में US टैरिफ का असर

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को संशोधित किया है। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए अनुमान 0.2 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया है, जबकि FY27 के लिए 6.2% रखा गया है। यह संशोधन अप्रैल-जुन तिमाही में 7.8% की मजबूत वृद्धि और घरेल् खपत की स्थिरता पर आधारित है, भले ही अमेरिकी टैरिफ जैसे वैश्विक कारकों का असर हो।

आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवियर गौरिनचास ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र की वृद्धि से चमक रही है। Q1 की गति FY26 को समर्थन देगी, लेकिन FY27 में व्यापार बाधाओं से धीमी गति संभव है। रिपोर्ट में जुलाई के अनुमान से FY26 के लिए 0.2% की बढ़ोतरी का उल्लेख है, जबकि FY27 में 0.2% की कटौती। वैश्विक विकास दुर 2025 में 3.0% और 2026 में 3.1% रहने का अनुमान है।

भारत की अर्थव्यवस्था FY25 में 6.5% बढ़ी। वर्तमान अनुमान सरकार के 6.3-6.8% के बीच है। वर्ल्ड बैंक ने FY26 के लिए 6.5% का अनुमान लगाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि GST दर कटौती और ग्रामीण मांग से वृद्धि बनी रहेगी। हालांकि, US टैरिफ से निर्यात प्रभावित हो सकता है। RBI ने FY26 के लिए 6.8% का अनुमान

यह अनुमान भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बनाता है। विशेषज्ञ चेताते हैं कि नीतिगत सतर्कता जरूरी है।



साफ़ान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज: पीएम मोदी ने हैदराबाद में भारत का पहला ग्लोबल MRO सेंटर का उद्घाटन किया

LEAP इंजनों के लिए विश्व का सबसे बड़ा रखरखाव केंद्र, 1,300 करोड़ निवेश से 1,000 नौकरियां; एविएशन सेक्टर को

नई उड़ान, विदेशी मुद्रा बचत

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जीएमआर एयरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क-एसईजेड में स्थित साफ़ान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (SAESI) सुविधा का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला ग्लोबल इंजन मूल उपकरण निर्माता (OEM) MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) केंद्र है, जो Airbus A320neo और Boeing 737 MAX विमानों के LEAP इंजनों की मरम्मत करेगा।

पीएम मोदी ने उद्घाटन समारोह में कहा, यह सुविधा भारत को वैश्विक MRO हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एविएशन क्षेत्र अब नई उड़ान भरने को तैयार है। उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान में भारत का 85% MRO कार्य विदेश में होता है, जिससे लागत बढ़ती है और विमान जमीनी लंबे समय तक खड़े रहते हैं। SAESI से विदेशी मुद्रा बचत होगी, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनेगी और 1,000 से अधिक

कुशल इंजीनियरों-तकनीशियनों को रोजगार मिलेगा। सुविधा में 45,000 वर्ग मीटर क्षेत्र है, जो सालाना 300 LEAP इंजनों की मरम्मत करेगी।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित थे। पीएम ने साफ़ान से डिजाइन इन इंडिया को बढ़ावा देने की अपील की। कंपनी ने 1,300 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश किया है, जो 2035 तक पूर्ण क्षमता पर पहुंचेगा। यह केंद्र भारत को एविएशन मरम्मत का वैश्विक केंद्र बनाने का प्रयास है। सरकारी नीतियां जैसे 2024 का GST सुधार, MRO गाइडलाइंस 2021 और नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 ने MRO प्रदाताओं के लिए कर संरचना सरल की है। पीएम ने कहा, "यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। तेलंगाना सरकार ने M88 मिलिट्री इंजन MRO का शिलान्यास भी किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत का एविएशन निर्यात बढ़ेगा।



एसबीआई का 3% NIM लक्ष्य सुरक्षित: RBI के 0.25% रेट कट पर भी चेयरमैन सीएस सेट्टी का भरोसा

अगले सप्ताह की MPC बैठक में कट की संभावना, लेकिन CRR कटौती और डिपॉजिट रीप्राइसिंग से लाभ; FY26 में RoA 1% से ऊपर का लक्ष्य

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का 3% नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहले ऊंची दरों पर बुक किए FD की रीप्राइसिंग, और 0.2% SB रेट रेट कट के बावजुद सुरक्षित रहेगा। बैंक के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, "RBI का निर्णय 5 दिसंबर की MPC बैठक में क्लोज कॉल होगा, लेकिन हमारा घरेलू अनुमान 0.25% के हल्के कट का है। इससे NIM पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं

सेट्टी ने बताया कि बैंक के 30% एसेट्स ही रेपो रेट से जुड़े हैं, इसलिए कट का असर सीमित रहेगा। NIM को मजबूत करने वाले कारक हैं: 1% CRR कटौती से लोनिंग के लिए अधिक संसाधन उपलब्धता,

(NIM) लक्ष्य अगले सप्ताह रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 0.25% रेपो कट का लाभ। Q2 में व्होल बैंक NIM 2.93% पर स्थिर रहा, जबिक डोमेस्टिक NIM 3.30% था। सेट्टी ने कहा, "फरवरी में कट बेहतर होता, क्योंकि तब FD रीप्राइसिंग का बड़ा हिस्सा होगा।" FY26 में RoA 1% से ऊपर रखने का लक्ष्य है, जो Q2 में 1.10%

रहा। सेट्टी ने कहा, वृद्धि 7.5% (Q2) और 7% (FY26) रहेगी, जबिक मुद्रास्फीति 0.29% पर स्थिर है। बैंक ने Q2 में लाभ 3% बढ़कर 18,641 करोड़ रुपये किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति SBI को मजबूत बनाएगी। शेयरों में 1% तेजी आई।



जानकारी |

टाटा मोटर्स: एसयूवी सेल्स 70% पार करेगी- शैलेश टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स एमडी शैलेश चंद्रा

नेक्सन-हैरियर-पंच की बिक्री में उछाल, EV सेगमेंट में 30% हिस्सेदारी; 2030 तक हर मॉडल में इलेक्ट्रिक वर्जन का लक्ष्य

नई दिल्ली: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा कि कंपनी की कुल बिक्री में एसयूवी का योगदान जल्द 70% से अधिक हो जाएगा। वर्तमान में यह 65-68% है। चंद्रा ने निवेशक सम्मेलन में कहा, हमारा पोर्टफोलियो तेजी से एसयूवी-केंद्रित हो रहा है। नेक्सन, हैरियर, सफारी और पंच की मजबत मांग से यह लक्ष्य FY26 के अंत तक हासिल हो जाएगा।

चंद्रा ने बताया कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का EV बाजार हिस्सा 30% के करीब है और कंपनी FY30 तक हर मॉडल का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। नेक्सन EV, कर्व EV और हैरियर EV अगले 12-18 महीनों में आएंगे। कंपनी ने FY25 की पहली छमाही में 2.8 लाख यूनिट्स बेचीं, जिसमें एसयूवी का योगदान 1.85

लाख था। अक्टूबर-नवंबर में हैरियर-सफारी की बिक्री 40% बढ़ी है।टाटा मोटर्स ने 10 नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिनमें 6 एसयुवी और 4 सेडान होंगे। कंपनी का लक्ष्य FY 30 तक 20 लाख यूनिट्स सालाना बिक्री है, जिसमें 50% EV होंगी। चंद्रा ने कहा, ग्राहक अब सुरक्षा, फीचर्स और डिजाइन में प्रीमियम एसयुवी चाहते हैं। हमारा फोकस उसी पर है।

विशेषज्ञों का मानना है कि टाटा मोटर्स का एसयुवी-ईवी कॉम्बिनेशन उसे मारुति, हंडई और महिंद्रा से आगे रखेगा। शेयर बाजार में टाटा मोटर्स के शेयर 2.8% चढ़कर 915 रुपये पर बंद हुए। यह रणनीति कंपनी को पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में नंबर-1 बनाने की दिशा में मजबुत कदम है।



Government Bolsters PSU Banking Leadership: New Executive Directors Appointed at Union Bank, Central Bank, and Bank of India

Three-Year Terms for Amresh Prasad, E Ratan Kumar, and Pramod Kumar Dwibedi; Aimed at **Enhancing Governance and Operational Efficiency**

New Delhi: In a strategic move to strengthen governance in public sector banking, the Government of India has appointed new Executive Directors (EDs) at Union Bank of India, Central Bank of India, and Bank of India, effective immediately for three-year terms.

At Union Bank of India, Amresh Prasad, previously Chief General Manager at Punjab National Bank, assumes the role of Executive Director. With over 32 years of experience in branch banking, corporate credit, and transaction surveillance, Prasad brings robust expertise to bolster the bank's operations.

Central Bank of India has elevated E Ratan Kumar, its former Chief General Manager, as Executive Director. Kumar, a B.E. in Computer Science holder with an MTech and Master of Financial Management from NMIMS, boasts nearly 35 years in core banking and IT, ensuring enhanced technological oversight.

Bank of India welcomes Pramod Kumar Dwibedi, also its ex-Chief General Manager, as ED. Dwivedi's three-decade career spans diverse roles across India and overseas, covering all banking verticals and administrative functions.

These elevations, recommended by the Financial Services Institutions Bureau (FSIB) in August 2025 after interviewing 80 candidates, align with the government's push for merit-based leadership in PSUs. The Appointments Committee of the Cabinet approved the proposals, filling vacancies in the 2025-26 panel year.

The changes come amid PSU banks' focus on digital transformation and credit growth, with combined advances exceeding Rs 80 lakh crore. Analysts view the appointments as timely for navigating economic headwinds. Shares of the banks traded flat, with Union Bank up 0.5% at Rs 151, Central Bank steady at Rs 45, and Bank of India gaining 0.8% to Rs 125 on BSE.

As India targets a \$5 trillion economy, these leadership infusions promise agile decision-making and innovation in the banking sector.





ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

[] (+91)7389912025 w visionadvisorymkt@gmail.com

How Corporate Earnings are Driving Nifty Toward 30,000?

India's stock market is moving with strong momentum, and one of the biggest reasons behind this rise is the sharp improvement in corporate earnings. When companies earn higher profits, their share prices rise, and this directly pushes market indices like the Nifty upward. Today, India is witnessing one of the strongest earnings cycles in more than a decade, and this steady performance is creating a solid foundation for the Nifty's journey toward the 30,000 level.

Corporate earnings simply refer to the profits a company makes after removing all expenses. When profits rise, investors feel confident, domestic and foreign funds invest more money, and the market moves upward. Over the last few years, Indian companies across banking, autos, manufacturing, infrastructure, defence, IT, and consumer goods have reported strong profit growth. This broad-based improvement is the real fuel behind the Nifty's current rally.

Banks and financial companies, which form the largest weightage in the Nifty, are showing exceptional performance. Low NPAs, strong credit demand, rising home loans, and better risk management have pushed their profits to all-time highs. Since banking companies contribute the maximum to the Nifty, their strong earnings make the index naturally stronger. As long as banks continue to

perform well, the foundation of the market remains stable.

The automobile and consumption sector is another major driver of earnings. With rising incomes, easy EMI availability, and aspirations of India's population, demand for cars, two-wheelers, electronics, and premium products has increased sharply. When people spend more, companies earn more. Higher demand has allowed auto companies and consumer brands to report good sales and profits, adding further strength to the Nifty.

Meanwhile, India's massive push toward infrastructure is creating long-term visibility for construction, earnings engineering. and capital goods companies. Highways, airports, metros, defence production, railways, smart-city projects are increasing order books and revenues for many listed companies. This is not a short-term trend; India plans to invest heavily infrastructure for the next two decades, which means steady earnings growth for companies involved in building the nation. The IT and technology sector also plays an important role in the Nifty. Despite global challenges, Indian IT firms continue to secure new contracts in cloud computing, digital transformation, cybersecurity, and artificial intelligence adoption. Their

stable margins and global presence provide strength and balance to the market during uncertain times.

All these factors together create a strong earnings environment, which is necessary for the Nifty to move toward higher levels 30,000. Stock markets sustainably only when company profits grow. Historically, whenever corporate earnings rise consistently, the market follows. If Indian companies continue to deliver 12-15% annual earnings growth, experts believe the Nifty reaching 30,000 is not just possible it is a natural outcome. India's economy is expanding, companies are performing well, and investors are becoming more confident. As long as earnings remain strong, the Nifty's upward journey is well-supported. In simple words, when Corporate India grows, every investor grows and the Nifty reflects that growth.

Dr. Irshad Ahmod Khan Sub-Editor



महिंद्रा का EV चार्जिंग नेटवर्क विस्तार: 2027 तक 250 स्टेशन स्थापित करने की योजना

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करने का प्रयास, 'मेक इन इंडिया' के तहत स्थानीय निर्माण; 2030 तक 10 GW EV क्षमता का लक्ष्य

मुंबई: मिहंद्रा एंड मिहंद्रा लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। कंपनी 2027 तक देशभर में 250 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी, जो EV अपनाने को गित देगी। यह घोषणा कंपनी के बोर्ड मीटिंग में हुई, जहां EV रोडमैप पर चर्चा की गई।

महिंद्रा के एमडी और सीईओ अनीश शाह ने कहा, भारत में EV क्रांति के लिए चार्जिंग नेटवर्क महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य हर 50 किलोमीटर पर एक स्टेशन सुनिश्चित करना है। योजना के पहले चरण में 100 स्टेशन 2026 तक तैयार होंगे, जो प्रमुख हाईवे, शहरों और पर्यटन स्थलों पर होंगे। स्टेशन DC फास्ट चार्जर (50-150 kW) से लैस होंगे, जो 30 मिनट में 80% चार्जिंग देंगे। कंपनी 'मेक इन इंडिया' के तहत स्टेशन स्थानीय स्तर पर ही बनाएगी, जिससे 500 नौकरियां सृजित होंगी।

महिंद्रा का EV पोर्टफोलियो XUV400, e-Verito और आगामी BE 6 की बिक्री FY25 में 25,000 यूनिट्स पार कर चुकी है। 2030 तक 10 GW EV क्षमता का लक्ष्य रखा है। शाह ने कहा, सरकारी PLI स्कीम और FAME-III से समर्थन मिलेगा। हम सोलर-इंटीग्रेटेड स्टेशन भी लाएंगे। चुनौतियां जैसे ग्रिड लोड और बैटरी लागत बरकरार हैं, लेकिन कंपनी ने 50% स्थानीय सोर्सिंग का लक्ष्य रखा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना भारत के 30% EV लक्ष्य (2030) को गति देगी। यह कदम EV पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा।



United Spirits Achieves 93% GHG Emission Cut, Surpasses Renewable Energy Goals in FY25 ESG Report

Diageo India Leads Alcobev Sector in Sustainability with 99% Renewable Use; Water Conservation and Diversity Initiatives Highlight Progress

New Delhi: Diageo India (United Spirits Ltd), a leading alcobev company, has reported a remarkable 93 percent reduction in greenhouse gas (GHG) emissions since 2020, as detailed in its fourth annual ESG Reporting Index for FY25. The report, released on Monday, also reveals the company has achieved 99 percent renewable energy usage across operations, well ahead of its 2030 targets.

This milestone stems from strategic shifts, including the elimination of coal use since 2022 by converting all distilleries to biomass-fuelled boilers. Supported by 2.7 MW of in-house solar capacity, Diageo India now relies almost entirely on renewables, slashing operational carbon footprints. Our Spirit of Progress ESG agenda builds a business that grows responsibly, leads with integrity, and creates long-term value, said Jitendra Mahajan, Chief Supply and Sustainability Officer. The index aligns with Global Reporting Initiative standards, UN Sustainable Development Goals, and Sustainability Accounting Standards Board disclosures.

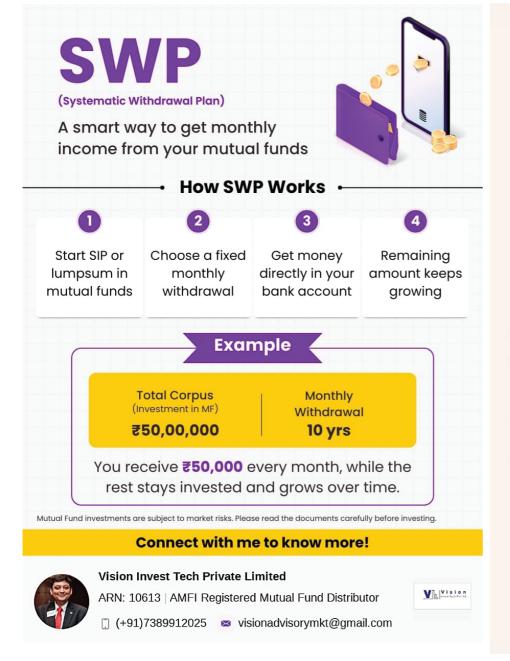
Water stewardship emerged as another success story, with the

Godavari Initiative restoring aquifers in water-stressed regions of Maharashtra, Uttar Pradesh, and Rajasthan.

Over 1 lakh trees have been planted to offset residual emissions, while afforestation efforts in Alwar under the 'Trees Outside Forest in Rajasthan' programme exceeded 2 lakh trees.

On the social front, women now comprise 28 percent of executives, 30 percent of the leadership team, and 50 percent of the executive committee progress toward a 50 percent female leadership goal. Diageo India earned Gold Employer status for LGBT+ Inclusion in 2024 from the India Workplace Equality Index. Governance remains robust, with a diverse board and quarterly executive reviews.

These advancements position Diageo India as a sustainability leader in the alcobev sector, amid India's push for net-zero by 2070. The report underscores how ESG integration drives performance, fostering climate-resilient communities and responsible consumption. As the company eyes further innovations in low-carbon technologies, its FY25 efforts set a benchmark for peers in a market valued at \$52 billion by 2027.





INVESTMENT AVENUES CALL FOR ARTICLES

Share Your Knowledge with INVESTMENT AVENUES

We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:

- 1. Article must be original
- 2. Submit in MS Word format
- 3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in

write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

जानकारी |

Adani Green Energy Expands Renewable Footprint with Two New Gujarat Subsidiaries

AHE13L and AHE16L to Focus on Solar, Wind Power Generation; Bolstering Integrated Clean Energy Ecosystem

Mumbai: Adani Green Energy Limited (AGEL), India's largest renewable energy company, has incorporated two new wholly-owned step-down subsidiaries to accelerate its clean energy expansion in Gujarat. The move, announced in a regulatory filing on Friday, aims to enhance generation, development, and distribution of renewable power, including solar and wind sources, as part of the group's ambitious net-zero strategy.

The subsidiaries Adani Hydro Energy Thirteen Limited (AHE13L) and Adani Hydro Energy Sixteen Limited (AHE16L) were established through AGEL's wholly-owned arm, Adani Saur Urja (KA) Limited (ASUKAL). Both entities, registered in Gujarat with an authorized and paid-up capital of Rs 1 lakh each, will engage in the full spectrum of renewable energy activities: generating, developing, transforming, transmitting, distributing, and selling power from wind, solar, and other clean sources. Operations are yet to commence, but they align with AGEL's goal of scaling to 45 GW by 2030.

This incorporation reflects our commitment to building an

integrated renewable ecosystem capable of supporting large-scale clean power deployment across India, a company spokesperson stated. Gujarat, a key hub for Adani's projects, already hosts over 10 GW of AGEL's operational capacity, including recent additions like the 408 MW solar park in Khavda.

The announcement comes amid AGEL's robust H1 FY26 performance, with operational capacity hitting 16.7 GW a 49% year-on-year increase and 50 MW new solar commissioning in Gujarat. Backed by the National Green Hydrogen Mission and PLI schemes, these subsidiaries could unlock further investments in hybrid projects, targeting 5 MTPA green hydrogen by 2030.

Shares of AGEL dipped 1% to Rs 1,019 amid broader market volatility, but analysts remain bullish, forecasting 20% revenue growth in FY26 driven by renewables. As India races toward 500 GW non-fossil capacity, Adani Green's Gujarat focus underscores the state's role in sustainable energy leadership, fostering jobs and economic growth.

JK Lakshmi Cement Pumps Rs 1,816 Cr into Chhattisgarh Mega Expansion

2.62 MTPA Integrated Unit at Raipur by 2028; Total Capacity to Surge to 20 MTPA, Eyes East India Demand Boom

New Delhi: JK Lakshmi Cement Ltd has approved a Rs 1,816 crore investment to set up a new 2.62 million tonnes per annum (MTPA) greenfield integrated cement plant in Raipur, Chhattisgarh, the company announced on Tuesday. The board cleared the project, which includes a 1.8 MTPA clinker unit and captive power facilities, with commercial production slated for Q1 FY28.

The expansion will boost JK Lakshmi's total cement capacity from 16 MTPA to over 20 MTPA, strengthening its footprint in the high-growth eastern and central markets. The plant will incorporate waste heat recovery systems, solar power, and advanced pollution control, aligning with the company's net-zero ambitions by 2050.

This strategic investment will enhance our presence in Chhattisgarh and neighbouring states where infrastructure spending is accelerating, said Vinita Singhania, Vice Chairman and Managing Director. The project is fully funded through internal accruals and debt, with no equity dilution planned.



Chhattisgarh offers proximity to limestone reserves and robust rail-road connectivity, enabling cost-efficient distribution to Odisha, Bihar, and Jharkhand. Analysts estimate the expansion will add Rs 1,200–1,400 crore to annual revenue post-commissioning. Shares of JK Lakshmi Cement rose 3.2% to Rs 852 on BSE following the announcement. With India's cement demand projected to grow

Shares of JK Lakshmi Cement rose 3.2% to Rs 852 on BSE following the announcement. With India's cement demand projected to grow 7–8% annually till 2030, the move positions JK Lakshmi to capture a larger slice of the Rs 2 lakh crore eastern market while reinforcing its premium brand portfolio.

Zydus Lifesciences Inks Exclusive Oncology Pact with US-Based RK Pharma for US Market Entry

Novel Sterile Injectable Supportive Care Product Under 505(b)(2) Pathway; N DA Filing Slated for 2026, Targets 6.2 Mn Unit TAM

New Delhi: Zydus Lifesciences Ltd, a alobal innovation-driven healthcare company, has entered into an exclusive licensing and commercialization agreement with RK Pharma Inc of the US for a novel sterile injectable 505(b)(2) oncology supportive care product targeting the US market. The partnership, announced on Tuesday via a regulatory filing, positions Zydus to expand its oncology portfolio amid growing demand for advanced supportive therapies.

Under the terms, RK Pharma will manufacture and supply the finished product, while Zydus will handle the New Drug Application (NDA) submission and commercialization in the US. The product, developed via the 505(b)(2) pathway, is expected to be filed in 2026. It promises a formulation designed tominimize dosing errors and improve compliance among healthcare professionals, addressing key

challenges in oncology supportive care. This partnership reinforces our commitment to delivering high-quality, affordable medicines and improving patient care, said Dr. Sharvil Patel, Managing Director of Zydus Lifesciences. The novel therapy targets a substantial commercial opportunity, with an estimated total addressable market (TAM) of 6.2 million units, per IQVIA MAT September 2025 data.

Ravishanker Kovi, Founder and Executive Chairman of RK Pharma, echoed the sentiment: Our collaboration with Zydus, a company with robust regulatory expertise and a powerful commercial footprint, ensures this important therapeutic option reaches patients efficiently. The deal leverages Zydus's strong US presence, where its specialty business has grown 25% YoY to \$150 million in Q2 FY26.

Zydus, with a global footprint across 50+countries, continues to diversify into high-value oncology and supportive care segments. This follows recent USFDA approvals for Verapamil ER tablets and other generics. Shares of Zydus rose 1.8% to Rs 1,120 on BSE, reflecting market optimism. As oncology treatments evolve toward precision medicine, this alliance could add \$100-150 million in annual revenue by FY28, analysts estimate, bolstering India's pharma exports amid a \$50 billion US oncology market.



Embassy Developments Aims for Rs 41,000 Cr GDV Milestone by 2028 with Kotak Debt Boost

Rs 1,500 Cr Loan for Bengaluru Office Projects; Pipeline Includes 20 Mn Sq Ft Mixed-Use Developments Amid Sector Rebound

Bengaluru: Embassy Developments, a flagship real estate arm of Embassy Group, has set an ambitious gross development value (GDV) target of Rs 41,000 crore by 2028, backed by a Rs 1,500 crore debt infusion from Kotak Real Estate Fund Management. The funding, secured on November 25, will fuel the execution of premium office and mixed-use projects in Bengaluru, the company's core market.

The loan, structured as a construction finance facility, supports Embassy's 20 million sq ft development pipeline, including the iconic Embassy 7th Central and Embassy TechZone expansions. This capital enables us to accelerate delivery

of world-class workspaces aligned with global sustainability standards, said Jitendra Virwani, Chairman, Embassy Group. With Bengaluru's office absorption hitting 15 million sq ft in H1 FY26 a 25% YoY rise the timing is opportune amid the city's IT-BT resurgence.

Embassy's strategy emphasizes Grade-A commercial assets, with 70% of the pipeline dedicated to LEED-certified offices catering to hyperscalers and Fortune 500 firms. The GDV goal reflects a 30% CAGR from FY25's Rs 20,000 crore bookings, driven by hybrid work models and data center demand. Kotak's investment underscores confidence in Embassy's 40 million sq ft portfolio, which

spans offices, residential, and retail. The deal arrives as India's commercial real estate attracts \$4.7 billion in institutional inflows in 2025, per Cushman & Wakefield. Embassy, with a debt-to-equity ratio of 0.5, maintains prudent leverage.

Shares of Embassy Office Parks REIT, a group entity, rose 1.8% to Rs 385 on BSE.

As urbanisation accelerates, Embassy's vision positions Bengaluru as Asia's innovation hub, creating 50,000 jobs and fostering sustainable growth. With RERA compliance and ESG focus, the developer eyes a Rs 1 trillion sector contribution by 2030.

जानकारी

NCR में लग्जरी होम्स की कीमतों में सबसे तेज उछाल: 72% की वृद्धि ने अन्य शहरों को पीछे छोड़ा

2022 से 2025 तक ₹13,450 से ₹23,100 प्रति वर्ग फुट, अनारॉक रिपोर्ट; प्रीमियम डिमांड और इंफ्रा विकास से बूम

मुंबई: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट ने रियल एस्टेट बाजार में धमाल मचा दिया है। अनारॉक रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से 2025 तक NCR में लग्जरी होम्स की औसत कीमतें 72% उछलकर ₹23,100 प्रति वर्ग फुट पहुंच गईं, जो देश के सात प्रमुख शहरों में सबसे अधिक वृद्धि है। यह उछाल ₹13,450 प्रति वर्ग फुट से शुरू होकर प्रीमियम लोकेशन, ब्रांडेड डेवलपर्स और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग से प्रेरित है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सात शहरों (मुंबई, दिल्ली-NCR, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता) में लग्जरी होम्स (₹1.5 करोड़ से ऊपर) की औसत कीमतें 2022 के ₹14,530 से बढ़कर 2025 में ₹20,300 प्रति वर्ग फुट हो गईं, जो 40% की वृद्धि दर्शाती है। NCR ने इस सेगमेंट में लीड किया, जबिक हैदराबाद (41%) और बेंगलुरु

(42%) दूसरे स्थान पर रहे। अनारॉक चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, लग्जरी होम्स की डिमांड अन्य सेगमेंट्स से तेज है, क्योंकि HNIs और NRIs बड़े घरों की तलाश में हैं। NCR में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो और एक्सप्रेसवे ने इसे आकर्षक बनाया।

जनवरी-सितंबर 2025 में सात शहरों में 2.87 लाख यूनिट्स बिकीं, जिनमें लगभग 30% लग्जरी थीं। NCR में गुरुग्राम ने 91% लग्जरी बिक्री का योगदान दिया। मिड-रेंज (₹40 लाख-₹1.5 करोड़) होम्स में 39% वृद्धि हुई, बेंगलुरु 62% के साथ टॉप पर। किफायती सेगमेंट में केवल 26% वृद्धि हुई, NCR 48% के साथ लीडर।

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती आय, शहरीकरण और RERA जैसे सुधारों से यह ट्रेंड जारी रहेगा। हालांकि, इनपुट कॉस्ट बढ़ने से कीमतें और चढ़ सकती हैं। NCR का यह बूम निवेशकों के लिए अवसर है।



TVS ILP ने आंध्र प्रदेश की सुविधा TBIS को लीज दी: टोयोटा ग्रुप की पहली रीजनल पार्ट्स सेंटर

विशाखापत्तनम में 33,000 वर्ग फुट का स्थान, दक्षिण भारत में पार्ट्स वितरण को मजबूती; स्थानीय रोजगार और सेवा समय में सुधार की उम्मीद

विशाखापत्तनमः TVS इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स पार्क्स (TVS ILP) ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित अपनी सुविधा का 33,000 वर्ग फुट से अधिक स्थान टोयोटा ग्रुप की कंपनी टोयोट्सु भारत इंटीग्रेटेड सर्विसेज (TBIS) को लीज पर दिया है। यह दक्षिण भारत में टोयोटा की पहली ग्लोबल पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर (RPC) स्थापित करने के लिए है। कंपनी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की, जो ऑटोमोटिव सेक्टर में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी।

TBIS, टोयोटा ग्रुप का हिस्सा, इस सेंटर के माध्यम से आंघ्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में टोयोटा जेनुइन पार्ट्स और एक्सेसरीज़ की उपलब्धता बढ़ाएगी। इससे सेवा समय कम होगा और ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। TBIS के डायरेक्टर प्रकाश नायर ने कहा, दक्षिण भारत हमारे लिए महत्वपूर्ण बाजार है, जहां ऑटोमोटिव डिमांड बढ़

रही है। विशाखापत्तनम का पोर्ट कनेक्टिविटी इसे साउथ और ईस्ट इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक हब बनाता है। यह सुविधा TVS ILP के कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाएगी, जो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को सपोर्ट करेगी।

TVS ILP, भारत का पहला कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स डेवलपर, ने कहा कि यह लीज दक्षिण भारत में उनकी उपस्थिति को मजबूत करेगी। जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर आदि कुमार ने कहा, हमारी टेक-एंडेबल्ड, बिल्ट-टू-सूट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती है। यह सेंटर स्थानीय रोजगार सृजित करेगा और विशाखापत्तनम के औद्योगिक विकास को गति देगा।

ऑटोमोटिव सेक्टर में बढ़ती मांग के बीच यह कदम महत्वपूर्ण है। टोयोटा भारत में अपनी सेवा नेटवर्क को विस्तार दे रही है। TVS ILP के पास देशभर में 42 लोकेशन्स पर पार्क हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पार्ट्स सप्लाई चेन मजबूत होगी। शेयर बाजार में TVS मोटर के शेयर 1.5% चढ़े।



जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को SEBI की मंजूरी: चार नए एक्टिव फंड लॉन्च करने को तैयार

जियो फाइनेंशियल और ब्लैकरॉक की जॉइंट वेंचर, डिजिटल इनोवेशन से रिटेल निवेशकों को लक्ष्य; 17,800 करोड़ NFO सफल, 2030 तक बड़ा विस्तार

मुंबई: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को चार नए एक्टिव म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (JFSL) और अमेरिकी एसेट मैनेजमेंट दिग्गज ब्लैकरॉक की 50:50 जॉइंट वेंचर, जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मई 2025 में SEBI से फाइनल रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया था। अब यह एक्टिव फंड्स जैसे इक्विटी, हाइब्रिड और थिमैटिक के माध्यम से भारतीय निवेशकों को आकर्षित करने को तैयार है।

कंपनी के MD और CEO सिंड स्वामीनाथन ने कहा, हम डिजिटल-फर्स्ट इनोवेशन ला रहे हैं, जो जियो के 50 करोड़ से अधिक टेलीकॉम कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड्स से जोड़ेगा। जुलाई 2025 में लॉन्च हुए तीन पासिव फंड्स ओवरनाइट, लिक्विड और मनी मार्केट के NFO में 17,800 करोड़ रुपये जुटाए गए, जिसमें 90 संस्थागत और 67,000 रिटेल निवेशक शामिल थे। ब्लैकरॉक का अलादीन प्लेटफॉर्म रिस्क मैनेजमेंट और इनसाइट्स देगा। SEBI की मंजूरी से जियो ब्लैकरॉक अब एक्टिव और पासिव दोनों फंड्स लॉन्च कर सकेगा। यह भारत के 72 लाख करोड़ के म्यूचुअल फंड बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, जहां जियो की डिजिटल पहुंच TER (टोटल एक्सपेंस रेशियो) को कम करने का दबाव डालेगी। इशा अंबानी, JFSL की नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा, यह साझेदारी भारत के युवा निवेशकों को सशक्त बनाएगी।"

कंपनी 2030 तक 1 लाख करोड़ AUM का लक्ष्य रखे हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि जियो की पहुंच से रिटेल भागीदारी बढ़ेगी। शेयर बाजार में JFSL के शेयर 1.5% चढ़े। यह कदम डिजिटल वेल्थ क्रिएशन को नई दिशा देगा।

INVESTMENT AVENUES®

Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In BhopaL

Discover genuine real estate and well-assessed business opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.

Secure Deals. Smart Investments.



WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1

Anil Bhardwai

Technical Head anil.stockcare@gmail.com

- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss
- Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	losing Rat	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	26203	26857	26584	26393	26120	25929	25656	25465
BANK NIFTY	59753	61432	60663	60208	59439	58984	58215	57760
SENSEX	85707	87891	86972	86340	85421	84789	83870	83238
FINNIFTY	27890	28858	28457	28173	27772	27488	27087	26803
MIDCAP	14044	14556	14325	14185	13954	13814	13583	13443
ACC	1851	2133	2059	1955	1881	1777	1703	1599
AXISBANK	1283	1343	1324	1303	1284	1263	1244	1223
ABCAPITAL	358	406	383	370	347	334	311	298
BHARTIARTL	2100	2222	2197	2148	2123	2074	2049	2000
BHEL	291	316	305	298	287	280	269	262
BIOCON	399	417	410	405	398	393	386	381
CDSL	1617	1703	1668	1642	1607	1581	1546	1520
	2971				2982			
DATAPATTERN	3809	3164	3107	3039	3767	2914	2857	2789
ESCORTS	7044	4240	4068	3939	7094	3638	3466	3337
EICHERMOTOR	258	7560	7421	7233	254	6906	6767	6579
FEDERAL BANK		277	268	263		249	240	235
GRINFRAPOJECT	1073	1144	1127	1100	1083	1056	1039	1012
HDFCBANK	1007	1058	1038	1022	1002	986	966	950
HCLTECH	1624	1691	1665	1645	1619	1599	1573	1553
HINDUNILVR	2468	2554	2512	2490	2448	2426	2384	2362
HAL	4540	4727	4638	4589	4500	4451	4362	4313
HYUNDAI	2328	2432	2390	2359	2317	2286	2244	2213
IOC	162	173	171	166	164	159	157	152
ICICIBANK	1388	1450	1424	1406	1380	1362	1336	1318
INFY	1558	1646	1615	1587	1556	1528	1497	1469
ITC	405	418	414	409	405	400	396	391
KOTAKBNK	2125	2232	2187	2156	2111	2080	2035	2004
LICHOUSING	550	571	565	557	551	543	537	529
LT	4073	4306	4223	4148	4065	3990	3907	3832
LUPIN	2081	2227	2159	2120	2052	2013	1945	1906
MARUTI	15890	16474	16342	16116	15984	15758	15626	15400
M&M	3761	3915	3842	3801	3728	3687	3614	3573
MGL	1199	1268	1252	1225	1209	1182	1166	1139
MAZGAONDOC	2678	2817	2774	2726	2683	2635	2592	2544
PFC	363	383	377	370	364	357	351	344
RECLTD	361	381	372	367	358	353	344	339
RELIANCE	1569	1648	1614	1592	1558	1536	1502	1480
SBIN	977	1026	1012	995	981	964	950	933
SUNPHARMA	1832	1920	1877	1854	1811	1788	1745	1722
SHRIRAMFINANCE	856	925	897	877	849	829	801	781
TITAN	3904	4036	3986	3945	3895	3854	3804	3763
TCS	3136	3237	3209	3172	3144	3107	3079	3042
TATAMOTORS	357	374	368	363	357	352	346	341
UPL	759	808	788	774	754	740	720	706
VALIENT	253	302	290	272	260	242	230	212
WIPRO	250	261	257	253	249	245	241	237

ओला के भविष अग्रवाल का नया दांव: घरेलू बैटरी स्टोरेज से टर्नअराउंड की उम्मीद

2026 में लॉन्च होगा 'ओला होम स्टोरेज', सोलर रूफटॉप के साथ बंडल; EV घाटे के बीच नई रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने

बेंगलुरु: ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक और सीईओ भविष अग्रवाल ने निवेशकों से कहा कि कंपनी 2026 में घरेल बैटरी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च करेगी, जो सोलर रूफटॉप के साथ बंडल बेचा जाएगा। Q2 अर्निंग कॉल में अग्रवाल ने इसे "गेम चेंजर" बताया और दावा किया कि यह उत्पाद ओला को नया टर्नअराउंड देगा। अग्रवाल ने कहा, हमने पिछले 2 साल में भारत का सबसे बड़ा EV ट्-व्हीलर प्लेटफॉर्म बनाया। अब अगला कदम घरों में एनर्जी स्टोरेज है। ओला होम स्टोरेज सोलर के साथ आएगा, जिससे बिजली बिल शून्य हो जाएगा और ग्रिड पर निर्भरता खत्म होगी। कंपनी का दावा है कि इसका बैटरी पैक मौजूदा EV बैटरी से 30-40% सस्ता होगा, क्योंकि गीगाफैक्ट्री में बड़े स्केल पर उत्पादन

यह घोषणा ऐसे समय आई है जब ओला इलेक्ट्रिक लगातार घाटे में है। Q2 में 564 करोड़ का नेट लॉस हुआ, जबिक रेवेन्यू 12% गिरकर 1,240 करोड़ रहा। सर्विस सेंटर और स्पेयर पार्ट्स की शिकायतों से ब्रांड इमेज को भी झटका लगा। अग्रवाल ने माना कि "पिछले 6 महीने चुनौतीपूर्ण रहे", लेकिन होम स्टोरेज और AI-संचालित रोबोटैक्सी (2026 लॉन्च) से कंपनी नई ऊंचाई छुएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में सोलर रूफटॉप की संख्या 2025 में 25 लाख पार कर चुकी है और बैटरी स्टोरेज की मांग तेजी से बढ़ रही है। यदि ओला सस्ता और भरोसेमंद प्रोडक्ट ला पाई तो यह टाटा पावर सोलर और एम्पीयर जैसे प्लेयर्स को कड़ी टक्कर देगी।



Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.